भारत में प्राकृतिक रंगीन कपास की खेती संघर्षरत

वैश्विक मांग के बावजूद केवल 200 एकड़ में हो रही खेती, सरकारी सहायता की दरकार

नयी दिल्ली, 20 जुलाई. भारत में प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास की खेती, वैश्विक मांग और दशकों से चल रहे सरकारी शोध प्रयासों के बावजूद, इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है. 1940 के दशक में तेजी से बढ़ रहा यह व्यवसाय अब कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल 200 एकड़ में ही सिमट कर रह गया है.

कम पैदावार मुख्य बाधा- हालांकि प्राकृतिक रंगीन कपास की कीमत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो सामान्य कपास (160 रुपये प्रति किलोग्राम) से 50 प्रतिशत अधिक है, लेकिन किसान इसकी खेती करने से हिचकिचा रहे हैं. इसका मुख्य कारण इसकी कम पैदावार है. आईसीएआर-केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीआई आरसीओटी) के प्रमुख वैज्ञानिक अशोक कुमार ने बताया, हल्के भूरे रंग के कपास की उत्पादकता बहुत कम यानी 1.5-2 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि सामान्य कपास की उत्पादकता 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ है. इसलिए किसान इस फसल की अधिक खेती नहीं करते हैं. कृषि वैज्ञानिक इस समय हल्के भूरे रंग के कपास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

भारत में रंगीन कपास की खेती 2500 ईसा पूर्व से हो रही है, जिसमें लाल, खाकी और भूरी किस्में शामिल थीं. हालांकि, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाली सफेद कपास की किस्मों पर जोर देने से रंगीन कपास हाशिये पर चला गया.

निर्यात की अपार संभावनाएं और अनुसंधान की कमी

कुमार ने कहा कि प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान में पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों से इसकी मांग बढ़ रही है. हालांकि, उत्पादन कम होने और बाजार की कमी के कारण कोई भी उन्नत किस्में विकसित नहीं कर पा रहा है. इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और चीन पारंपरिक प्रजनन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में उत्पादन और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए और अधिक सरकारी सहायता की आवश्यकता है, ताकि इस पर्यावरण-अनुकूल फसल की खेती को पुनर्जीवित किया जा सके.

स्विफ्ट भुगतान मानक में देरी से बढ़ेगा जोखिम : आईबीए

नयी दिल्ली, 20 जुलाई. भारतीय बैंक संघ ने सभी बैंकों से स्विफ्ट आईएसओ-20022 मानदंडों के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा है.आईबीए ने कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें सीमापार भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. ऋणदाताओं के लिए आईएसओ-20222 लेनदेन की मात्रा की निगरानी के लिए पर्याप्त बफर समय सुनिश्चित करने को अगस्त, 2025 तक स्थानांतरण शुरू करना आवश्यक है. आईबीए के मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल ने हाल में सभी बैंकों के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में यह बात कही.आईएसओ-20022 वित्तीय संदेश के लिए एक वैश्विक मानक है, जिसे सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सीमापार भुगतान के लिए अपना रहा है.

एनएलसी इंडिया 2026 में लाएगी बड़ी आईपीओ

सीसीईए से मिली विशेष मंजूरी, 7,000 करोड़ निवेश को हरी झंडी

हरित ऊर्जा विस्तार पर होगा 50-60 हजार करोड़ रुपये निवेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई एनआईआरएल के अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है.

कंपनी का लक्ष्य अपनी विस्तार योजनाओं के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये जुटाना है. एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली ने बताया कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 1.4 गीगावाट से बढ़ाकर 10 गीगावाट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. कंपनी की योजना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की है. उन्होंने बताया कि कंपनी 2026-27 की पहली तिमाही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दस्तावेजों का मसौदा दाखिल करने की योजना बना रही है.

मोटुपल्ली ने कहा, हम आई.पी.ओ. के जरिए 4,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बना रहे हैं. इसलिए सितंबर तक हम एनआईआरएल के माध्यम से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों को बढ़ाने की स्थिति में होंगे और मार्च, 2026 तक हम कानूनी और वित्तीय जांच-परख पूरी कर लेंगे और 2026-27 की पहली तिमाही में हम सेबी के पास आवेदन करेंगे.एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग सात गुना बढ़ाने के लिए 50,000-60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

कंपनी का इरादा यह राशि इक्विटी और ऋण के माध्यम से जुटाने का है. उन्होंने कहा कि इक्विटी वाला हिस्सा आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 16 जुलाई को एनएलसी इंडिया लिमिटेड को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को नियंत्रित करने वाले निवेश दिशानिर्देशों से विशेष छूट दी है. इससे एनएलसीआईएल अब एनआईआरएल में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी. कंपनी अब बिना किसी अनुमोदन के सीधे या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने में भी सक्षम होगी. सार्वजनिक क्षेत्र की सभी नवरत्न कंपनियों के लिए यह मंजूरी आवश्यक होती है.

जुलाई में एफपीआई का मिला-जुला रुख

मुंबई, 20 जुलाई (वार्ता) विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 69.6 करोड़ डॉलर (5,939 करोड़ रुपये) का शुद्ध निवेश किया है.आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महीने के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयरों में बिकवाली कर डेट खरीदे. इक्विटी में उन्होंने 64.3 करोड़ डॉलर की बिकवाली की जबकि 134.4 करोड़ डॉलर के डेट की लिवाली की. इसके अलावा म्यूचुअल फंड में उन्होंने 4.6 करोड़ डॉलर लगाये जबकि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट से पांच करोड़ डॉलर निकाले.इस महीने की शुरुआत में (एफपीआई) निवेशकों का रुख सकारात्मक था, हालांकि बाद में वे बिकवाल हो गये, खासकर पिछले सप्ताह. इससे पहले जून में एफपीआई निवेशक बिकवाल रहे थे.

रिलायंस ने कमाई का बनाया नया रिकॉर्ड

तिमाही लाभ 76.5 प्रतिशत बढ़कर रु. 30,783 करोड़

जियो का ईबीआईटीडीए रु. 18,135 करोड़

नई दिल्ली, 20 जुलाई. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में बेहतरीन नतीजे दर्ज करते हुए अपने अब तक के सर्वोच्च समेकित ईबीआईटीडीए और लाभ की घोषणा की है.

कंपनी का समेकित राजस्व 6% की सालाना वृद्धि के साथ रु.2.73 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जो उपभोक्ता व्यवसायों की मजबूती को दर्शाता है.रिलायंस का समेकित ईबीआईटीडीए 35.7% की छलांग लगाकर रु. 58,024 करोड़ हो गया, जो कंपनी का अब तक का सर्वोच्च स्तर है. वहीं कर-पश्चात समेकित लाभ 76.5% बढ़कर रु.30,783 करोड़ हो गया है.पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने रु.29,875 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया. 30 जून 2025 तक कंपनी का शुद्ध ऋण मामूली बढ़कर रु.1.17 लाख करोड़ हो गया.

कंपनी ने जियोगेम्स क्लाउड की शुरुआत की है, जो एक अत्याधुनिक क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है. इस पर स्मार्टफोन, लैपटॉप या सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए 500 से अधिक गेम्स की सुविधा दी जा रही है.जियो का औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) रु.208.7 हो गया है. प्रति ग्राहक डेटा खपत 37 जीबी प्रतिमाह रही. कुल डेटा ट्रैफिक 24% बढ़कर 54.7 अरब जीबी हो गया है.

रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (जियो-बीपी) के आउटलेट्स की संख्या 1,991 हो गई है. एचएसडी की बिक्री में 34.2% और एमएस में 38.6त्न की सालाना वृद्धि हुई है.

तेल एवं गैस सेगमेंट का राजस्व 1.2% घटकर रु.6,103 करोड़ और ईबीआईटीडीए 4.1% घटकर रु.4,996 करोड़ रहा. केजीडी 6 गैस उत्पादन में गिरावट तथा रखरखाव लागत बढ़ने को इसके पीछे कारण बताया गया है.

केजीडी6 का औसत उत्पादन 26.55 एमएमएससीएमडी गैस और 19,300 बैरल प्रतिदिन तेल/कंडेनसेट रहा. सीबीएम के दूसरे चरण में ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी उत्पादन दर लगभग 0.90 एमएमएससीएमडी है.

नेतृत्व की प्रतिक्रिया

रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने कहा कि, यह तिमाही जियो के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है. हमने 5जी और होम ब्रॉडबैंड सेवाओं को सशक्त बनाया है. जियोगेम्स क्लाउड और जियोपीसी जैसे डिजिटल उत्पादों ने हमारी तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाया है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि, हमने तकनीकी नवाचार, भौगोलिक विस्तार और बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिला.

स्टेबलकॉइन कानून से बाजार में हलचल

मुंबई 20 जुलाई (वार्ता) लगातार तीन सप्ताह की गिरावट के बाद अगले सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करने में घरेलू स्तर पर कंपनियों के तिमाही परिणाम और वैश्विक स्तर पर अमेरिका में स्टेबलकॉइन को लेकर बने नये कानून की अहम भूमिका होगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को गाइडिंग एंड इस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यू.एस. स्टेबलकॉइन्स% (जीनियस) एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये जिसका असर सोमवार को बाजार खुलते ही दिखेगा. खासकर स्टेबलकॉइन जारी करने वालों के लिए शत-प्रतिशत रिजर्व रखने के प्रावधान से डॉलर और अल्पावधि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की मांग बढ़ेगी और ये मजबूत होंगे. इससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं. अमेरिका द्वारा नये टैरिफ को लेकर अंतिम समझौते से पहले निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं और उनका यह रूख आगे भी जारी रहने की संभावना है.

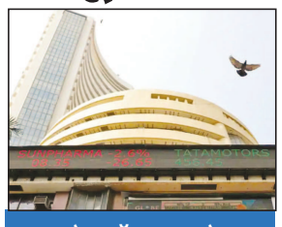

स्टेबलकॉइन कानून से डॉलर होगा मजबूत

विदेशी निवेशक निकाल सकते हैं पूंजी

सप्ताह के दौरान 21 जुलाई को इटरनल, 23 जुलाई को इंफोसिस और 25 जुलाई को बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के परिणाम जारी होने हैं. आईडीबीआई, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों के परिणाम भी सप्ताह के दौरान जारी होने हैं.

सिएट को दहाई वृद्धि की उम्मीद

मानसून बेहतर, ग्रामीण बिक्री में तेजी की उम्मीद

नयी दिल्ली, 20 जुलाई.टायर विनिर्माता कंपनी सिएट लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष (2025-26) में घरेलू पुराने वाहनों में टायर बदलने के खंड (रिप्लेसमेंट), विशेष रूप से ग्रामीण बाजारों से दहाई अंक में वृद्धि की उम्मीद है.

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनंब बनर्जी ने कहा कि इससे बिक्री बढ़ेगी. हालांकि, वाहन विनिर्माता कंपनियों को सीधी आपूर्ति कम रहने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि कंपनी अमेरिका में शुल्क की स्थिति पर भी नजर रख रही है, जो एक बड़ा विकासशील बाजार है, लेकिन अभी उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है.कंपनी ने आगे चलकर देश में अपने विस्तार की दिशा तय करने के लिए अमेरिका पर भी नजर रखी है.

उन्होंने कहा, हमने पहली तिमाही में दहाई अंक की वृद्धि के साथ शुरुआत की है, जिसे हमने पिछले साल भी बनाए रखा था. उम्मीद है कि अगली दो-तीन तिमाहियों में यह वृद्धि बरकरार रहेगी या इसमें तेजी आएगी.

परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा

2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, कानूनों में होगा बदलाव

नई दिल्ली, 20 जुलाई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत असैन्य परमाणु क्षेत्र में निवेश को लेकर वैश्विक स्तर पर निजी क्षेत्र की आशंकाओं का समाधान करेगा. देश में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला गया है.

परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रभार भी संभालने वाले सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आसान बनाने के लिए प्रासंगिक नियमों और कानूनों में बदलाव करने होंगे, जिन पर इस समय सरकार का कड़ा नियंत्रण है. उन्होंने कहा कि आम बजट में इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नियम और संभावित कानून बनाने होंगे, जिसके लिए बहुत विचार-विमर्श और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम सहित प्रमुख कानूनों में संशोधन करने की घोषणा की थी.

समाचार विशेष

तेजप्रताप व राजद के बीच दूरी और निकटता का अंतर्द्वंद्व

तेजप्रताप को राजनीतिक भविष्य की चिंता

पटना. तेजप्रताप यादव और राजद के साथ अभी दूरी और निकटता का अंतर्द्वंद्व है, क्योंकि दोनों अभी ऊहापोह में हैं. तेजप्रताप को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, जो राजद के सहयोग के बिना अधर में प्रतीत हो रहा है.

राजद को तेजप्रताप से बगावत की आशंका है, जिसके कारण पिछले वर्षों में हल्की खरोंच लग चुकी है. इसीलिए दोनों ओर से अभी इतनी गुंजाइश छोड़ी जा रही कि साथ-बात हमेशा के लिए बेपटरी न हो जाए.

तेजप्रताप को अभी एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की तलाश है, जहां से जीत की गारंटी हो. अभी तक की चुनावी स्थिति में किसी मजबूत गठबंधन के भीतर ही यह अभिलाषा पूरी हो सकती है. विधानसभा के पिछले दो चुनावों में वे क्रमशः महुआ और हसनपुर से विजयी रहे हैं. इस बार तय नहीं कर पा रहे कि कहां दांव आजमाएं, क्योंकि राजद से टिकट की अभी गारंटी नहीं. इसीलिए वे दोनों विधानसभा क्षेत्रों की परिक्रमा कर रहे. दोनों जगह अपने समर्थकों को ढांढस बंधा रहे, लेकिन प्रत्यक्षतः परिवार या पार्टी पर आक्षेप की कोई बात नहीं कर रहे. अलबत्ता अपना पुराना राग दोहरा रहे कि परिवार और पार्टी को कुछ जयचंदों ने अपने प्रभाव में ले लिया है. भविष्य तेजस्वी का है, जिनका सारथी बनकर वे चुनावी कुरुक्षेत्र में उनके विजय की कामना रखते हैं.

राजद के पास दो विकल्प

तेजप्रताप अगर बगावत-विरोध पर नहीं उतरे तो उनके लिए राजद के पास दो विकल्प हैं. विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर पार्टी में उनकी वापसी या फिर महागठबंधन में अपने खाते से किसी एक सीट पर प्रत्याशी नहीं देकर उनका मार्ग प्रशस्त कर देना. बहरहाल, तेजप्रताप का मन महुआ पर अधिक है, जहां से वे 2015 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. महुआ से अभी मुकेश कुमार रौशन राजद के विधायक हैं. लालू-तेजस्वी के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन का वे कोई अवसर नहीं चूकते.

राजद के निशाने पर नीतीश कुमार नहीं भाजपा

पटना. बिहार में कमाल की राजनीति हो रही है. जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियों की राजनीति साफ होती जा रही है. एक तरफ जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं, जिनका सारा हमला राजद के साथ साथ जदयू और नीतीश कुमार पर है.

वे भाजपा को निशाना नहीं बना रहे हैं. तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने अब एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को निशाना बनाना बंद कर दिया है. नीतीश पर हमला हो भी रहा है तो सरकार के कामकाज को लेकर, खास कर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. नीतीश के ऊपर निजी हमले बंद हो गए हैं. पार्टी के सभी नेताओं से कह दिया गया है कि वे भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करें या सरकार पर सवाल उठाएं. इसका कारण यह नहीं है कि राजद को उम्मीद है कि नीतीश उसके साथ आ जाएंगे. इसका कारण यह है कि नीतीश पर निजी हमले से राजद को नुकसान की संभावना दिख रही है.

अश्वनी शर्मा की ताजपोशी से बदलेगी राजनीति

जालंधर. पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा की ताजपोशी से प्रदेश की राजनीति में नया बदलाव आने की आहट सुनाई देने लगी है. पठानकोट से विधायक अश्वनी शर्मा तीसरी बार प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं.

पार्टी में पिछले कुछ माह से जमीनी स्तर के नेताओं से लेकर टकसाली भाजपाई काफी असहज महसूस कर रहे थे. पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़ अपने पद से त्यागपत्र दे चुके थे और प्रदेश भाजपा के सदस्यता अभियान से लेकर तमाम मीटिंगों से दूरी बनाकर चल रहे थे. पार्टी की महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा की सक्रियता व उपस्थिति काफी कम हो चुकी थी. अश्वनी शर्मा को जिम्मेदारी मिलने से टकसाली भाजपाई खुश हैं.

कालिया से है अश्वनी की निकटता- वहीं, अश्वनी शर्मा की निकटता पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के साथ काफी है. लिहाजा कालिया गुट का दबदबा पंजाब भाजपा की राजनीति में दोबारा बढ़ सकता है. साल 2010 में जब प्रो. राजिंदर भंडारी के स्थान पर नए भाजपा प्रधान की खोज चल रही थी तो सबसे अधिक रेस अश्वनी शर्मा व कमल शर्मा के बीच चल रही थी. कालिया का सिक्का तब दिल्ली तक खूब चलता था. कालिया ने अश्वनी शर्मा को प्रदेश प्रधान बनाकर न केवल अश्वनी शर्मा का कद ऊंचा करवाया बल्कि पठानकोट से तत्कालीन मंत्री मास्टर मोहन लाल व होशियारपुर से तीक्षण सूद व कमल शर्मा की टीम को किनारे लगा दिया था. तब से अश्वनी शर्मा व कालिया के बीच खासा तालमेल बना हुआ है. वहीं, संगठन महामंत्री श्रीनिवासलू का पूरा समर्थन अश्वनी शर्मा की टीम को मिलेगा. श्रीनिवासलू व जाखड़ के बीच खासी ठनी हुई थी.

विशेष भाजपा ने खेला सबसे चौंकाने वाला पत्ता!

2026 में केरल जीतने की तैयारी

तिरुवनंतपुरम. केरल की राजनीति में एक नई हलचल उस वक्त पैदा हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता सी सदानंदन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया. ये वही सदानंदन हैं, जिन्होंने कन्नूर जिले की राजनीतिक हिंसा में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे.

भाजपा के इस कदम को सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि राज्य में अपने इरादों और रणनीति का बड़ा इशारा माना जा रहा है. भाजपा अब यह दिखाना चाहती है कि वह सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि सीपीएम (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सवादी) को चुनौती देने वाली असली विपक्षी ताकत है.

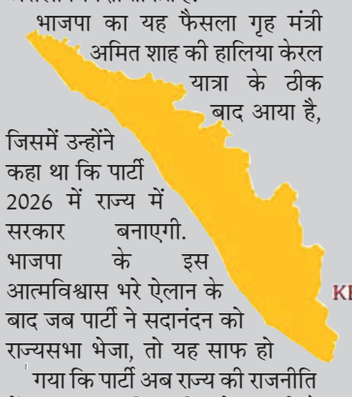

भाजपा का यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की हालिया केरल यात्रा के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी 2026 में राज्य में सरकार बनाएगी. भाजपा के इस आत्मविश्वास भरे ऐलान के बाद जब पार्टी ने सदानंदन को राज्यसभा भेजा, तो यह साफ हो गया कि पार्टी अब राज्य की राजनीति में आक्रामक भूमिका निभाने जा रही है. यह कदम सिर्फ एलडीएफ (वाम गठबंधन) और यूडीएफ (कांग्रेस गठबंधन) के लिए चौंकाने वाला नहीं रहा, बल्कि इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर गया है. भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा सीपीएम की हिंसा की शिकार नहीं है, बल्कि वह जनता के बीच से निकली वो ताकत है जो उसे हराने के लिए लड़ रही है. उन्होंने सदानंदन के पुराने बयान को दोहराते हुए कहा—हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं. इस तरह भाजपा यह बताना चाह रही है कि वह अब पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि सीपीएम को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है.

कांग्रेस और लेफ्ट को मिला चेतावनी का संकेत

जब से सदानंदन की नियुक्ति हुई है, तब से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों भाजपा पर हमलावर हैं. वे इसे संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण कहकर विरोध कर रहे हैं. लेकिन भाजपा यह साफ कर रही है कि वह अपने हिंदुत्व के विचार से कोई समझौता नहीं करेगी और न ही पीछे हटेगी. राजनीतिक विश्लेषक जे प्रभाष के मुताबिक भाजपा अब यह जताना चाहती है कि केरल में सिर्फ वही पार्टी है, जो सीपीएम को खुली चुनौती दे सकती है.

क्या भाजपा के लिए राह आसान होगी?

राजनीतिक जमीन पर हालांकि भाजपा के लिए राह आसान नहीं है. प्रभाष का कहना है कि केरल की मौजूदा स्थिति में भाजपा का असर सीमित है. राज्य में अभी भी सीपीएम को एझावा और अनुसूचित जाति जैसे बड़े वर्गों का समर्थन हासिल है, जिससे उसे मजबूत जनाधार मिलता है. इसके अलावा, राज्य की करीब 50 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की है—मुस्लिम और ईसाई समुदाय, जो आमतौर पर भाजपा का समर्थन नहीं करते.

आरएसएस कार्यकर्ताओं को मिला भरोसा- सदानंदन की नियुक्ति को भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा हौसला माना जा रहा है. खासकर उत्तर केरल, जहां सीपीएम का मजबूत दबदबा है, वहां आरएसएस कार्यकर्ताओं को अब उम्मीद है कि वे खुलकर संगठन को खड़ा कर पाएंगे. सदानंदन जैसे नेता, जिन्होंने निजी जीवन में बड़ी कुर्बानी दी है,.

बाहरी नेताओं के बल चल रही थी पार्टी

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक संगठन में टकसाली भाजपाई काफी असहज महसूस कर रहे थे. पार्टी बिना प्रधान के चल रही थी. बूथ स्तर तक की कमेटियों के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा था. इसलिए पार्टी का कार्यकारी प्रधान लगाना जरूरी हो गया था. अश्वनी शर्मा तीसरी बार प्रधान की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं. उनकी जमीनी स्तर पर खासी पकड़ है. महिला मोर्चा की प्रधान से लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष तक में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है. पार्टी का एससी मोर्चा भी कमजोर हो चुका है.